आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरूवार 14.11.2024
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा –– सरकार वर्ष 2025 तक राज्य की डेढ लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है।
- "पी०एम० सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना'' के तहत प्रदेश भर में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के घरों पर अब तक साढे सात हजार से अधिक सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
- पर्वतीय क्षेत्रों में जोखिम मूल्यांकन और चुनौतियां विषय पर देहरादून में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया।
- मुख्यमंत्री ने कहा– सरकार, पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को लेकर गंभीर, पलायन रोकथाम के लिए विभिन्न योजनाओं पर किया जा रहा है काम।

ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार वर्ष 2025 तक राज्य की डेढ लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। चमोली जिले के भराड़ीसैंण में आयोजित राज्यस्तरीय ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यशाला में श्री धामी ने कहा कि सरकार पहले ही दिन से सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर चल रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब नज़र आने लगे हैं। पिछले तीन साल के दौरान स्वरोजगार के क्षेत्र में कई काम हुए हैं और अब महिलाएं तथा युवा स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने लगे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते अब तक प्रदेश में एक लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी है।

कार्यशाला में विभिन्न जिलों से आए ग्रामीण उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने ग्रामीण उद्यमिता को लेकर अपने अनुभव व्यक्त किए और आवश्यक सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कार्यशाला में प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से अमल करते हुए, ग्रामीण उद्यमियों की सभी समस्याओं का समाधान निकालेगी।

रूफ टॉफ सोलर संयत्र

उत्तराखण्ड को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई दिशा देने की राह में प्रदेश में घरों पर रूफ टॉप सोलर संयत्रों की स्थापना की जा रही है। "पी०एम० सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना'' के तहत रूफ टॉप सोलर संयत्रों की स्थापना के लिए यूपीसीएल नोडल इकाई के रूप में काम कर रहा है।

प्रदेश भर में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के घरों पर लगभग 30 मेगावाट क्षमता के कुल सात हजार पांच सौ 92 सोलर रूफ टॉप संयंत्र स्थापित कर लिए गए हैं। इस योजना का लाभ लेने वालों को अब तक लगभग 48 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी जा चुकी है। रूफ टॉप संयंत्र लगाने के लिये प्रदेश में 300 से अधिक वेन्डर्स पंजीकृत हैं जिनका विवरण pmsuryaghar.gov.in पर भी उपलब्ध है।

सफलता

एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों ने डायबिटिक गेस्ट्रोपैरीसिस की दवा खोजने में सफलता हासिल की है। क्लीनिकल ट्रायल में दवा सफल रहने के बाद इसे पेटेंट मिल गया है और जल्द ही दवा बाजार में उपलब्ध होगी। डायबिटिक गेस्ट्रोपैरीसिस की दवा बनाने के लिए प्रोफेसर रविकांत को बेस्ट रिसर्चर का पुरस्कार मिला है। एम्स के जनरल मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रविकांत ने बताया कि करीब तीन साल के शोध के बाद यह दवा तैयार की गई है। जिन मरीजों में डायबिटिक गेस्ट्रोपैरीसिस की समस्या थी उन्हें आठ सप्ताह तक सुबह शाम यह कैप्सूल खिलाई गई जिसके बाद इन मरीजों में महत्वपूर्ण सुधार देखे गए। दवाई बंद करने के बाद छह माह तक इन मरीजों की निगरानी की गई। छह माह बाद इन मरीजों में गेस्ट्रोपैरीसिस की जांच की गई तो नाममात्र के लक्षण पाए गए।

बल दिवस

आज बाल दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों, विशेषकर बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनांए दी हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और देश के बेहतर भविष्य के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना सबकी जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के बेहतर कल के लिए बच्चों का वर्तमान सुरक्षित होना आवश्यक है। बच्चों के संतुलित और समग्र विकास से ही हम देश और समाज को खुशहाल बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बाल अधिकारों के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

अमेरिकन वर्ल्ड पुलिस गेम्स

उत्तराखंड पुलिस के उपनिरीक्षक मुकेश पाल 17 नवंबर से कोलंबिया में आयोजित होने वाले 11वें लेटिन अमेरिकन वर्ल्ड पुलिस खेल 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह पॉवर लिफ्टिंग में भारत से चयनित एकमात्र खिलाड़ी हैं। मुकेश पाल पहले भी कनाडा वर्ल्ड पुलिस गेम्स में दो रजत पदक और बेंगलुरु ओपन नेशनल चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीत चुके हैं।

राष्ट्रीय सेमिनार

पर्वतीय क्षेत्रों में जोखिम मूल्यांकन और चुनौतियां विषय पर देहरादून में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। हिमालयन सोसायटी ऑफ जियोसाइंटिस्ट और उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (यू.एल.एम.एम.सी) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सेमिनार का उद्देश्य आपदा से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों के प्रति समझ को बढ़ाना और जोखिमों को प्रभावी रूप से कम करने के लिए रणनीति विकसित करना था। सेमिनार में सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने आपदा से निपटने और इससे बचाव के लिए पूर्व तैयारियों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आपदाओं के लिहाज से उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्य बेहद संवेदनशील हैं और इसे ध्यान में रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपदा के तीन चरण होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण आपदा पूर्व तैयारी का है। आपदाओं का सामना करने के लिए जितनी अच्छी तैयारी होगी, प्रभाव उतना ही कम होगा।

श्री सुमन ने कहा कि आपदाओं का सामना करने के लिए गोल और रोल दोनों स्पष्ट होने जरूरी है। भारत सरकार ने आईआरएस सिस्टम बनाया है, जिसे अपनाकर यह दोनों लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में विभिन्न आपदाओं से लड़ने में रिस्पांस टाइम कम हुआ है।

पलायन रोकथाम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार, पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन की समस्या को लेकर गंभीर है और इसे रोकने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के भराडीसैंण में पलायन निवारण आयोग की अहम बैठक में श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इस बैठक में पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा के साथ ही इसके निवारण के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर मंथन किया गया। सदस्यों ने पलायन निवारण के लिए विभागीय सहयोग से अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य करने की बात रखी। पहाड़ों से हो रहे पलायन के प्रमुख कारणों पर चर्चा के दौरान बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन निवारण आयोग द्वारा दिए जा रहे सुझावों को अमल में लाने के लिए संबंधित विभागों के माध्यम से ठोस कार्य योजना बनाई जा रही है।

स्वच्छता

चमोली जिले की सभी नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि नदियों में जाने वाले कचरे और गंदे नालों का ट्रीटमेंट किया जाए। विधानसभा परिसर, भराड़ीसैंण में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चमोली को एक स्वच्छ और आदर्श जिले के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। श्री धामी ने विभागों को अपने कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी गेस्टहाउसों में भी विशेष स्वच्छता का ध्यान रखा जाए।

महिला आयोग

महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने चमोली जिला कारागार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयोग की अध्यक्ष ने महिला कैदियों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अध्यक्ष ने महिला कैदियों को खाने–पीने के लिए दिया जाने वाला भोजन, चिकित्सकीय उपचार व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला कारागार में महिला कैदियों के लिए सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने के निर्देश दिये।

एक नज़र समाचार पत्र की सुर्खियों पर––

सर्वोच्च न्यायालय के तय काननी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमानी बुलडोजर कार्रवाई की ख़बर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण की ख़बर है– मनमाने तरीके से नहीं चलेगा बुलडोजर, आरोपित या दोषी होने के आधार पर नहीं हो सकती कार्रवाई, देना होगा 15 दिन का नोटिस। इसी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है– जज नहीं बन सकते अधिकारी.... आरोपी हो या दोषी, बिना उचित प्रक्रिया घर नहीं गिरा सकते।

ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में पलायन और भूकानून पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में हुए मंथन को भी सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है– परगना और हितधारकों के सुझावों से बनांएगे भू–कानून। हिंदुस्तान की ख़बर है– जन भावनाओं के अनुरूप बनाया जा रहा सख्त भू–कानून, सख्त भू–कानून के लिए एसडीएम और तहसीलदार स्तर तक से लिए जांएगे सुझााव।

हिंदुस्तान समाचार पत्र ने देहरादून में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर ख़बर दी है– संकटः दून में बढ़ा प्रदूषण, एक्यूआई 300 के करीब, दून में वायु प्रदूषण का स्तर पांच दिन से खराब श्रेणी में बरकरार, सांस और दिल के मरीजों समेत सामान्य लोगों को दिक्कत।